www.himalayanupdate.com 7018631199 समाचार पत्र Postal Regd no: HP/128/SML/2020-22

नवंबर, 2023

आपकी आवाज़

हिमालयन अपडेट

RNI-HPHIN/2017/73579

7018631199 शुक्रवार 17.11.2023 पृष्ठ: 01, मूल्य: 1 रू. शिमला से प्रकाशित advthimalayanupdate@gmail.com

किफायती दरों में अपना विज्ञापन प्रकाशित करें और अपने व्यापार को और ऊंचाईयों पर ले जाएं। संपर्क करें: 7018631199

अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में हमें लिखें।

himalayanupdate@gmail.com

मुख्यमंत्री ने दिए सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश

शिमला/हिमालयन अपडेट
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ गत दिवस आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की और प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर एक मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है तथा विभाग इस योजना को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के दृष्टिगत इसकी रूपरेखा शीघ्र तैयार करे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं

को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यहां के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। राज्य सरकार सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से स्थापित इकाइयों से 25 वर्ष के लिए बिजली की खरीद करेगी, जिससे युवाओं को आय के स्थाई स्रोत प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार 40 प्रतिशत सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार का यह सक्रिय दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा, बल्कि विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अग्रणी बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ावा दे रही है और वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार ने अपना पहला बजट भी हरित बजट के रूप में प्रस्तुत किया है।ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों का पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उत्पादन महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ई-वाहनों के संचालन को भी बढ़ावा दे रही है तथा आने वाले समय में इससे प्रदेश में बिजली की मांग और बढ़ेगी। उन्होंने 21 नवंबर को भी ऊर्जा विभाग की दोबारा बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड हरिकेश मीणा, हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभ करण सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

झूठ बोल रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री: बिंदल

शिमला/हिमालयन अपडेट
मुकेश अग्निहोत्री उप-मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिन्दल ने कहा कि मुकेश का बयान झूठ का पुलिंदा है जिसमें उन्होनें गारंटियां पूरी करने की बात कही है। 2022 के चुनाव में गारंटियों पर गारंटियां देते चले गए और बोलते समय सांस भी नहीं लिया कि कितनी गारंटियां दी जा चुकी है। डॉ बिन्दल ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश के हर गांव, हर गली, हर गूचे की दीवारों को गारंटियों के लेखों से भर दिया गया और चिल्ला चिल्लाकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में गारंटियां पूरी करेंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गारंटियों पर भाषण देते समय प्रियंका गांधी से लेकर हर छोटे बड़े नेता कहते नहीं थकते थे कि बस सरकार कांग्रेस की बने और पहली कैबिनेट में सब कुछ कर दिया जाएगा परन्तु सरकार बनने

के बाद जो नेता दिल्ली से आये थे, दूसरे प्रांतों से आए थे वो तो अपना भाषण झाड़ कर चले गए और जिनके हाथ में सत्ता की चाबी आई वो गारंटियां पूरी करने के मामले में फिर दोबारा से हिमाचल की जनता को धोखा देने में जुट गए है। डॉ. बिन्दल ने कहा कि पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी कांग्रेस के सभी नेताओं ने दी जिसके वीडियो घर घर पहुंचाए गए। आज लगभग एक साल सरकार को बने हुए हो गया एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी गई अपितु दस हजार के आस पास लोगों को जिन्हे पूर्व भाजपा सरकार ने नौकरी दी थी, नौकरी से निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी स्थाई नौकरी देने की बात करती रही और अब दोबारा से ठेके पर नौकरियां देने के प्रस्ताव पारित हो रहे हैं और वन विभाग में जो कर्मचारी लगाने का प्रस्ताव है उनके लिए तो न अनुबंध नीति है और न ही कोई अन्य नीति है। बेरोजगारों के अलावा महिलाओं को, किसानो को, गरीबों को, युवाओं को, कर्मचारियों को जो गारंटियां दी गई वो सब लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि प्रदेश के हर व्यक्ति के पास कांग्रेस के नेताओं के भाषण की कॉपियां हैं इसलिए जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता।

ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/हिमालयन अपडेट
चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश सरकार की प्रतिनिधि उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने गत दिवस राज भवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने आपसी सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि पर्यटन, संस्कृति, पर्यावरण के अतिरिक्त हिमाचल एवं ब्रिटेन शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग से कार्य करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर विचारों एवं ज्ञान का आदान-प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने प्रदेश में की जा रही प्राकृतिक खेती के बारे में भी अवगत करवाया। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें हिमाचली टोपी एवं शाल भेंट कर सम्मानित भी किया।

पीएम मोदी ने दिया सम्मान, कांग्रेस ने समझा वोट बैंक: जम्वाल

शिमला/हिमालयन अपडेट
भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्त एवं विधायक राकेश जम्वाल ने कहा की देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौमुखी विकास किया है। भारत ने विश्व स्तर पर एक नई पहचान हासिल की है। उन्होंने कहा की पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम जनमन के माध्यम से देश के सभी आदिवासियों को बड़ा फायदा हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के साढ़े सात दशकों तक वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए 24 हजार करोड़ रू की परियोजना का शुभारंभ किया है। आज से पहले देश

में कभी ऐसा नहीं हुआ, यह निर्णय एतिहासिक है।उन्होंने कहा की सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सडक, दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर आधारित इस मिशन से इस वर्ग को विशेष लाभ होगा। आज से पहले कांग्रेस पार्टी ने केवल मात्र इस पत्र को एक वोट बैंक समझा इसके ऊपर कुछ भी नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस वर्ग को लेकर केवल मात्र राजनीतिक सेकने का कार्य किया। उन्होंने कहा की आयुष्मान भारत योजना, सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन, टीबी उन्मूलन, सौ फीसदी टीकाकरण, पी एम सुरक्षित मातृत्व योजना, पी एम मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, जन धन योजना सहित विभिन्न योजनाओं के सम्पूर्ण कवरेज पर फोकस रखा गया है । पीएम मोदी की केंद्र सरकार ने पिछले साढ़े नौ साल से जनजातीय कल्याण के लिए अडिग प्रयास किए है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंतीए 15 नवम्बर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित की गई। देश भर में 10 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किये जा रहे हैं। भाजपा सरकार के दौरान जनजातीय समुदायों के लिए 50 लाख से अधिक पक्के आवास बनेए 1.3 करोड़ नल कनेक्शन मिले और 1.5 करोड़ शौचालय बने। आयुष्मान योजना के तहत 95 लाख आयुष्मान कार्ड बने, साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में जन औषधि केन्द्रों से सस्ती और अच्छी दवाई उपलब्ध करवाई गई। जनजातीय समुदाय को सिकल सेल अनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्रीय मिशन लागू किया गया। एकलव्य स्कूलों की स्वीकृति में साढ़े साथ गुना वृद्धि हुईए 2004-2013 में 90 स्कूलों के मुकाबले 2014-2023 में करीब 700 स्कूल मिशन वन धन के तहत खोले गए है। 61 हजार स्वयं सहायता समूहों के जरिये 11 लाख जनजातीय भाई बहन लाभान्वित हुए है। उन्होंने कहा की यह केवल पीएम मोदी की अथक मेहनत और परिश्रम के कारण हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेताओ ने इस प्रकार की सोच कभी रखी ही नहीं, केवल वोट बैंक की राजनीति पर फोकस रखा।

सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा टीम ने गांव कुंगड़त में मादक पदार्थों की लत से बचने के बताए तरीके

हमीरपुर/हिमालयन अपडेट
हर समय अपने दोस्तोंए रिश्तेदारों और हितैषियों के साथ रहे। जब आप उनके सामने हर समय रहेंगे तो आपको नशा करने का मौका ही नही मिलेगा।

नशे से ग्रस्त रोगियों को रोज डायरी लिखनी चाहिये। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। जीवन की हर एक बात लिखनी चाहिये। नशा करने के बाद के दुष्परिणामों को लिखने से व्यक्ति को आभास होता है की किस तरह उसकी जिन्दगी नशे से खराब हो रही है। नशीले पदार्थो का सेवन कुछ मिनटों के लिए आनन्द देता है पर इसके दूरगामी दुष्परिणाम होते है। यह व्यक्ति को धीरे धीरे निगल जाता है और उसके जीवन को हर तरह से

बर्बाद कर देता है। ऐसे लोग आये दिन लोगो से झगड़ा करने लगते है, ऑफिस या कार्यस्थल पर साथी कर्मचारियों के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार शुरू कर देते है।

नशीले पदार्थो के सेवन से बचाव के विभिन उपाय

काम करते हुए दुर्घटना ग्रस्त हो जाना, सस्पेंड होना, बार-बार नौकरी बदलना, नौकरी छोड?ा, चिड़चिड़ा और गुस्सैल स्वभाव दिखाने से व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है। व्यक्ति के बुरे दिन शुरू हो जाते है। अतः हमे नशीले पदार्थो का सेवन बिलकुल नही करना चाहिये। जो लोग इस समस्या से ग्रस्त है उनको दृढ़ निश्चय करके इसे छोड़ देना चाहिये। याद रखे नशा एक जहर है। अपने मन में नशे की लत को छोडने की ठान लीजिये मन में प्रबल इच्छा होना जरूरी है केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन मे संचालित अस्पताल-साँसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा की हरोली टीम ने डॉ प्रदीप के नेतृत्व मे राजकीय वरिष्ठ विद्यालय कुंगड़त में स्थानीय विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया।पुनर्वास केंद्रध नशा मुक्तिकेंद्र में भर्ती होना अच्छा विकल्प है। वहां पर और भी लोग आते है। सबका इलाज एक साथ डॉक्टरों की देख रेख में किया जाता है। समूह चिकित्सा में मरीज का इलाज किया जाता है। स्वास्थ्य जांच शिविर मे बच्चों के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच की गई व रक्तजांच भी की गई। इस दौरान 70 बच्चों की ब्लड ग्रुप जांच भी की गई । मनोवैज्ञानिक पद्धति से रोगी का इलाज किया जाता है। बच्चों को उपयुक्त उपचार सलाह एवं दवाईयों का वितरण भी निरूशुल्क किया गया द्य इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा वर्कर एवं स्थानीय अध्यापक भी मौजूद रहे।ध्यान और योग के द्वारा भी मादक पदार्थो की लत को छोड़ा जा सकता है। सभी ने इस स्वास्थ्य शिविर के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व प्रयास संस्था का धन्यवाद किया।

'प्रासंगिक सूचनाएं आज के समय की जरूरत'

मंडी/हिमालयन अपडेट
प्रेस दिवस के अवसर पर डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया विषय पर चर्चा की गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के महत्व पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी, एडीएम डॉ मदन कुमार, उप निदेशक सूचना एवं सम्पर्क मंडी जोन मंजुला सहित जिला स्तर के पत्रकार उपस्थित रहे। इस वर्ष भारतीय प्रेस परिषद ने चर्चा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया विषय दिया था।उपायुक्त ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेस सहित कृषि तक में प्रभाव पड़ रहा है। मीडिया भी इससे अछूता नहीं रह पाया हैं। इसके कुछ बुरे तो कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। वर्तमान दौर में सूचनाओं के अत्यधिक प्रवाह के कारण प्रासंगिक सूचनाएं आज के समय की जरूरत हैं। फेक सूचनाओं की पड़ताल एआई के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कुछ काम खत्म हो जाते हैं परन्तु इससे नई संभावनाएं भी पैदा होती हैं। उन्होंने पत्रकारों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि इससे नुकसान कम और फायदे ज्यादा हैं। पत्रकारिता के लिए यह प्रासंगिक है। एडीएम मदन कुमार ने कहा कि मानवीय बुद्धिमत्ता का कृत्रिम बुद्धिमत्ता कभी 100 प्रतिशत स्थान नहीं ले सकती है। उन्होंने इसके सकारात्मक उपयोग करने पर बल दिया। चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार बीरबल शर्मा, मुरारी शर्मा, मुनीष सूद, खेम चंद शास्त्री, डीसी वर्मा, डीपी गुप्ता, पुरषोतम शर्मा और रूप उपाध्याय ने भाग लिया। उप-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, क्षेत्रीय कार्यालय मंडी मंजुला कुमारी ने उपायुक्त तथा मीडिया से जुड़े कर्मियों का प्रेस दिवस के इस जिला स्तरीय समारोह में भाग लेने पर स्वागत किया।

उन्होंने बताया कि जीवन के सभी पहलुओं सहित पत्रकारिता का क्षेत्र भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। मीडिया जगत में लेखन, संपादन, एंकरिंग, प्रस्तुतीकरण तक के सभी कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकों फायदों के साथ काफी चुनौतियां भी सामने आई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से समय की बचत, दर्शकों को जोडने की क्षमता में वृद्धि, गलतियों की गुंजाइश कम, डाटा उपलब्धता, पूर्वाग्रह की समस्या की समाप्ति आदि कई फायदे हैं लेकिन इस तकनीक के प्रयोग से प्राकृतिक मानवीय स्पर्श का अभाव, पत्रकारिता के क्षेत्र में नौकरियों की कमी, सृजनात्मकता का आभाव, गहन रिपोर्टिंग की कमी आदि अनेक खामियां भी हैं। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में एक संतुलन बना कर आगे बढ? की जरूरत है।

विधायक बबलू ने 36 निराश्रित बच्चों को वितरित किए पात्रता प्रमाण पत्र

ऊना/हिमालयन अपडेट
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वीरवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अंब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत 36 निराश्रित बच्चों को पात्रता प्रमाण पत्र वितरित किए। विधायक बबलू ने कहा कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन आफ द स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया है। इस योजना के तहत सरकार ने प्रदेश के करीब 6,000 निराश्रित बच्चों को गोद लिया है। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र से 52 निराश्रित बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इस मौके पर एसडीएम अंब विवेक महाजन, डीएसपी डा. वसुधा सूद, सीडीपीओ अंब विजय कुमार, ब्लॉक कांग्रेस चिंतपूर्णी के अध्यक्ष डा. रविंद्र कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विकास कश्यप, प्रदेश कांग्रेस ओबीसी कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य नरेश बरोटिया, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राघव ठाकुर, पूर्व उपप्रधान अंब धरमिंदर कुमार, राज कुमार गौतम, रितेश शर्मा, निशा शर्मा, अधिवक्ता सौरव शर्मा, सीता राम व संदीप शर्मा आदि मौजूद रहे।

18 से 25 दिसंबर को हो सकता है विधानसभा सत्र: कुलदीप सिंह पठानिया

शिमला/हिमालयन अपडेट
धर्मशाला में आयोजित होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं।इस बाबत सरकार की ओर से दो प्रस्ताव आये हैं।कैलेंडर ईयर में आयोजित होने वाले इस सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने भी हामी भरते हुए कहा कि विधानसभा सचिवालय पूरी तरह तैयार है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा सभा अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार कि ओर से दो प्रस्ताव आये हैं। विधानसभा सचिवालय इसे आयोजित करवाने के लिए पूरी तरह तैयार है।शीतकालीन सत्र कैलेंडर ईयर साल में ही पूर्ण करना होता है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 11 दिसंबर से 17 दिसंबर और 18 दिसंबर से 25 दिसंबर का

जिक्र किया है।

प्रदेश सरकार जब चाहे इन प्रस्तावित तिथियों में इसे आयोजित करवा सकती हिमाचल है।उन्होंने कहा कि कैलेंडर ईयर में ही शीतकालीन सत्र करवाना होता है। नए वर्ष में बजट सत्र का आयोजन भी होता है जिसमें प्रदेश सरकार के 1 साल का लेखा जोखा महामहिम राज्यपाल द्वारा अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया जाता है। इस कारण हिमाचल प्रदेश विधानसभा 18 दिसंबर से 25 दिसंबर तक होने की पूर्णतया संभावना है।